PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Bhaskar, Faridabad
Sunday, 27th February 2011, Page: 5
Width: 12.66 cms Height: 13.84 cms, Ref: pmin.2011-02-27.45.20

राजस्थान, मप्र और उप्र में सेहत के आंकड़े दुरुस्त नहीं

प्रदीप सुरीन. नई दिल्ली

देश में सेहत के मामले में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी भी पिछड़ी नजर आ रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ताजा कॉमन रिव्यू मिशन-4 रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले चार साल से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में यहां अभी भी शिशु मृत्युदर और मातृ मृत्युदर के मामले में आंकड़े बहुत खराब हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि इन तीन राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों और डाक्टरों की कमी अभी भी बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि शिशु मृत्युदर में अभी भी मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। वहां प्रति हजार शिशुओं के जन्म पर करीब 67 नवजातों की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रति हजार शिशुओं में से 63 और राजस्थान में 59 नवजातों की मौत हो रही है। रिपोर्ट बताती है कि 2009 में 13,25,600 नवजातों की मौत में से 26.6 फीसदी उत्तर प्रदेश से थे। इन कुल मौतों में से 9.8 प्रतिशत नवजात मध्य प्रदेश और 8.1 फीसदी शिशु राजस्थान से थे।

रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के पब्लिक हेल्थ सेंटरों में अभी भी 61 फीसदी विशेषज्ञ और 50 फीसदी सामान्य डाक्टरों की कमी है। मध्य प्रदेश चार साल से स्वास्थ्य योजना का हिस्सा होते हुए भी 53 फीसदी स्टाफ नर्सों की भरपाई नहीं कर पाया है। राजस्थान का हाल भी कुछ इसी तरह का है, राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बनी हुई है। जिलों और गावों में स्वास्थ्य संबंधि योजनाएं अभी भी लंबित हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की हालत सबसे बुरी है। रिपोर्ट बताती है कि यहां मातृत्व स्वास्थ्य के मामलें में राज्य को अभी काफी बेहतर करने की जरूरत है। महिलाओं के डिलीवरी के लिए अभी भी नई तकनीक नहीं लागू हो पाई है।

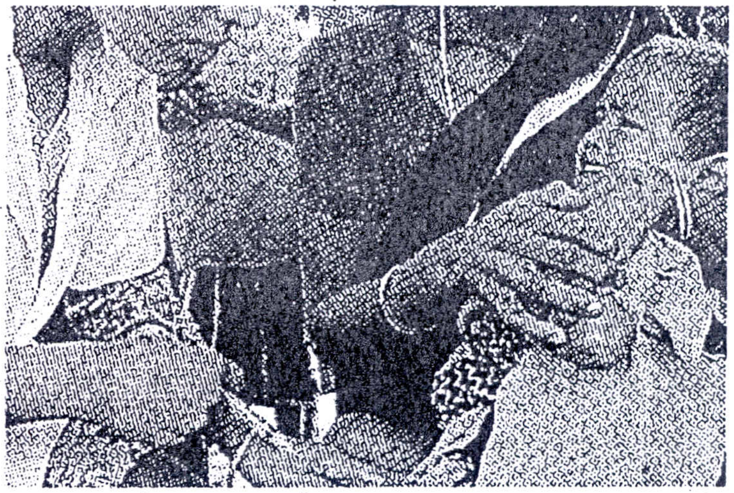

कॉमन रिव्यू मिशन-4 की रिपोर्ट में आशा वर्करों की स्थिति में भी सुधार की जरुरत पर प्रकाश डाला गया है। अभी भी कई राज्यों में आशा वर्करों को की ट्रेनिंग को लेकर सही मानदंड नहीं है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को सही समय पर वेतन नहीं दिया जाना भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है। गांव-गांव जाकर आशा कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी नहीं हो पाना भी एक समस्या है।